SHRIMATI LAKSHMI MENON: It was pointed out the other day that the survey operations have already begun on the 1st of October.

बर्मा द्वारा भारतीय कपड़े की खरीद

*२११. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा की सरकार ने भारत से कुछ कपड़ा खरीदने के बारे में पूछ-ताछ की थी; यदि ऐसा है तो विभिन्न श्रेणियों का कितना कपड़ा बर्मा सरकार यहां से खरीदना चाहती है ;

(ख) इस कपड़े की कीमत का भुगतान नकदी के रूप में होगा अथवा किसी अन्य रूप में होगा ; और

(ग) बर्मा में भारतीय कपड़े की खपत बढ़ाने के लिये सरकार क्या क्या प्रयत्न कर रही है और इसमें उसे कितनी सफलता मिली है ?

†[PURCHASE OF INDIAN CLOTH BY BURMA

*211 SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister for COMMERCE AND CONSUMER INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Burma had made enquiries from the Government of India for the purchase of cloth from India, and if so, what is the quantity of cloth of different quanlities which the Government of Burma propose to purchase;

(b) whether the price of the cloth is to be paid by that Government in cash or in some other shape; and

(c) what steps Government are taking to increase the consumption of Indian cloth in Burma and how far they have succeeded in that direction ?

†English translation.

व्यापार मंत्री (श्री डी. पी. करमरकर) : (क), (ख) और (ग). एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां ; (१) बर्मा सरकार का खुले टेन्डर द्वारा जितना कपड़ा खरीदने का प्रस्ताव है, उसका परिमाण यह है–

५६,८२,१४८ गज ।

(२) बर्मा द्वारा कपडे की और खरीद, बर्मा के आयातकों और भारतीय निर्यातकों के बीच बातचीत करके की जा रही है । इसमें प्रगति हो रही है ।

(ख) इस कपड़े की कीमत ३८,५०,००० अमेरिकी डालर की अमेरिकी रुई दे कर चुकायी जायगी । यह रुई अमेरिकी पब्लिक ला ४८० के अधीन दी जायगी ।

(ग) (१) विदेशों को भारतीय सूती कपड़े का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार की सहायता से सूती वस्त्र निर्यात सम्वर्द्धन परिषद् विशेष रूप से बना दी गयी है। इस परिषद् ने जून-जुलाई १९५५ में एक वस्त्र प्रतिनिधि-मंडल दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को भेजा था जिसका उद्देश्य इन देशों को हमारा निर्यात बढ़ाने की संभावनाएं देखना था। यह प्रतिनिधि-मंडल बर्मा भी गया था।

(२) सूतीवस्त्र निर्यात सम्वर्द्धन परिषद ने रंगून में एक अफसर नियुक्त कर दिया है, जिसका काम वहां के बाजार का सवक्षण करना तथा वे उपाय तथा तरीके सुझाना है जिनसे बर्मा को हमारा निर्यात बढ़ सके। भारतीय सूती कपड़े के संभावित बर्मी खरीदारों को यह अफसर हर संभव सहायता देता है।

(३) फरवरी १९५६ में बर्मा से एक खरीद मिशन भारत आया था और उसने ६०–७० लाख गज कपड़ा खरीदा था।

(४) हाल ही में भारत सरकार ने बर्मा तथा सं. रा. अमेरिका से एक त्रिपक्षीय करार किया था। इस करार के अधीन भारत सरकार बर्मा संघ*को लगभग २।। करोड़ गज कपड़ा निर्यात करने की व्यवस्था करेगी। हाल ही में भारत सरकार ने बर्मा संघ की सरकार से "नया व्यापार करार" नाम से एक नया व्यापार

करार भी किया है इस कारर के अनुसार दोनों सरकारों ने वे जरूरी कदम उठाने का निश्चय किया है, जिससे दोनों देशों के बीच हुए व्यापार को संतुलित किया जा सके। यह आशा की जाती है कि इस करार के अन्तर्गत बर्मा परम्परागत वस्तुओं जैसे कपडे आदि का बड़े परिमाण में आयात करेगा।

†[THE MINISTER FOR TRADE (SHRI D. P. KARMARKAR): (a), (b) and (c). A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Yes Sir; (i) the quantities of cloth proposed to be purchased by the Government of Burma by open tender are as under :—

59,82,148 yards.

(ii) Further purchases by Burma are being effected by negotiations between the importers in Burma and exporters in India. This is under progress.

(b) The price of the cloth is to be paid in American Cotton of the value of 3,850,000 American Dollers, under U.S. P.L. 480.

(c) (i) The Cotton Textiles Export Promotion Council, is specially set up with the assistance of the Government to boost up export of Indian Textiles to foreign countries. This Council sponsored a Textile Delegation to the South East Asia Countries in JuneJ July 1955 to explore the possibilities of increasing our exports to these countries. The delegation visited Burma also.

(ii) The Cotton Textiles Export Promotion Council has posted an overseas officer at Rangoon whose duty it is to survey the market there and suggest ways and means to increase our exports to Burma. Every assistance is being given by this Officer to prospective buyers of Indian Textiles in Burma.

(iii) In February 1956 a Burmese Purchase Mission visited India and effected purchases of 6-7 million yards of cloth.

(iv) Recently the Government of India have entered into a Tripartite Agreement with the Governments of U.S.A. and Burma. According to this agreement the Government of India will arrange the exports to the Union of Burma of about 25 million yards of cloth. The Government of India have also entered into a new agreement called "New Trade Agreement" with the Government of Union of Burma recently. Under this agreement, the two Governments have decided to take necessary steps to balance the trade between the two countries. It is expected that under this Agreement Burma would be importing large quantities of traditional items *viz.*, cloth etc.]

श्री नवाब सिंह चौहान : आपने रंगून में जो अधिकारी व्यापार की देखभाल करने के लिये रखे हैं उन्होंने बर्मा मे हमारे कपड़े की खपत को बढ़ाने के लिये क्या विशेष काम किये हैं ?

श्री डी. पी. करमरकर : यह तो बड़ा सवाल है, जनाब, जिसके जवाब में मुझे बहुत कुछ कहना होगा। इस चीज को देखने के लिये हमारा एम्बेसेडर वहां है, कोमर्शियल सैक्रेटरी भी है, और जैसा मैंने बताया है, हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का भी एक अधिकारी वहां है। अभी तक हालत यह थी कि एंग्लो बर्मीज एग्रीमेंट के मुताबिक हमें जो कंसेशन मिले हुए थे वे उन्होंने विथड्रा कर लिये है, इसलिये हमें यह दिक्कत पैदा हुई।

श्री नवाब सिंह चौहान : क्या यह सच है कि बर्मा की सरकार ने भारतीय व्यापारी संघ से बर्मा में कपड़े की मिलें खोलने के लिये कहा है ? अगर यह बात सच है तो इन मिलों के खुल जाने से भारत से जो कपडा वहां जाता है, उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री मोरारजी देसाई : यह बात सच है कि वे लोग हमारे व्यापारियों के साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन यह गवर्नमेंट के तौर पर नहीं है। परन्तु अगर वे वहां मिल खोलना चाहें तो क्या हम ऐसा कहें कि आप अगर मिल खोलेंगे

†English translation.

तो हमारा माल नहीं जायगा। हमारे साथ ऐसा व्यवहार कोई करे तो क्या होगा ? इसलिये इस तरीके से इस सवाल को नहीं देखना चाहिये।

श्री नवाब सिंह चौहान : मैं सिर्फ सूचना चाहता था कि उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? मैं तो चाहता हूं कि और ज्यादा मिलें वे खोले।

श्री मोरारजी देसाई : क्या असर होगा, यह तो साफ है। वहां मिल खुलेंगी तो यहाँ का कपड़ा वहां नहीं जायगा।

SHRI H. C. DASAPPA: May I know, Sir, how it happens that in a tripartite agreement between India, Burma and the U.S.A., the question of export of cloth to Burma has arisen ? What place has America in that agreement ?

SHRI D. P. KARMARKAR: That is a separate item by itself, in addition to the agreement that now subsists between India and Burma, by which we expect that a larger amount of cloth will be lifted from here for Burma. This is a special agreement so that we might import a certain specified quantity of cotton from the United States and export either cloth or yarn as the Burmese Government requires. This is absolutely a separate agreement and it gives employment to our mills.

SHRI KISHEN CHAND: We have given every help, credit facilities to Burma and we purchase their rice. May I know from the hon. Minister whether there is a proposal to have a sort of bilateral agreement with Burma to sell our cloth in exchange for rice and various other commodities that we take from them ?

SHRI MORARJI DESAI: We are trying to see that there is complete trade balance between Burma and India.

SHRI MAHESWAR NAIK: May I know, Sir, whether some new trade agreement has been arrived at between Burma and India for export of cloth ?

SHRI D. P. KARMARKAR: That is exactly what my esteemed senior colleague referred to.

SHRI M. VALIULLA: I want to know whether there are any additional facilities placed at the disposal of the other countries which make them sell cloth to Burma at the expense of India.

SHRI D. P. KARMARKAR: No, Sir.

NAHAN FOUNDRY PRIVATE LTD.

*212. SHRIMATI SAVITRY DEVI NIGAM: Will the Minister for HEAVY INDUSTRIES be pleased to state:

(a) the output, in tons, of the Nahan Foundry Private Ltd., in the years 1949-50 and 1953-54; and

(b) the amount invested by Government in the company after it was taken over by Government from the Maharaja of Sirmur?

THE MINISTER FOR HEAVY INDUSTRIES (SHRI MANUBHAI SHAH) (a) and (b): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) The output of the Nahan Foundry in the years 1949-50 and 1953-54 was 1355 tons and 1040 tons respectively.

(b) Government have not invested any amount in the Foundry, after it was taken over from the Maharaja of Sirmur. Certain amounts were, however, advanced to the foundry, details of which are given below: —

Year	Amount of Loan Rs.
1952-53 . . .	4 lakhs
1953-54 . . .	3·5 lakhs
1954-55 . . .	75,000
1955-56 . . .	75,000

The last two loans have since been repaid by the foundry.